

भारत राजपत्र

The Gazette of India

प्रताधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रांक्षार से प्रदानित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 327] नई दिल्ली, सोमवार, चून 7, 1971/ज्येष्ठ 17, 1893

No. 327] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 7, 1971/JYAISTA 17, 1893

इस भाग में भिन्न-पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह भलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 7th June 1971

S.O. 2279/18A/IDRA/71.—Whereas the Central Government is of the opinion that the Ajudhia Textile Mills Ltd., Delhi, an industrial undertaking in respect of which an Investigation has been made under Section 16 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, is being managed in a manner highly detrimental to public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 18-A of the said Act, the Central Government hereby authorises the National Textile Corporation Limited, Delhi, (hereinafter referred to as the Authorised Controller) to take over the management of the whole of the said undertaking, namely, the Ajudhia Textile Mills Ltd., Delhi, subject to the following terms and conditions, namely:

- (i) The Authorised Controller shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government; and
- (ii) The Authorised Controller shall hold office for five years from the date of publication in the Official Gazette of this Order. The Central Government may terminate the appointment of the Authorised Controller earlier, if it considers necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of five years commencing on the date of its publication in the official Gazette.

[No. F 9(8)/Lic.Pol./71]
S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

श्रीधोगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय

(श्रीधोगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 7 जन, 1971

का० अ० 2279/18ए/आई डी आर ए/71:— यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अयुध्या टैक्सटाइल मिल्स लि०, दिल्ली नामक एक श्रीधोगिक उपक्रम का, जिसके सम्बन्ध में श्रीधोगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 15 के अधीन जांच की गई, प्रबन्ध इस ढंग से किया जा रहा है जो सार्वजातिक हित में बहुत ही अहितकार है;

अतः, जब उपरोक्त अधिनियम की धारा 18-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एवं द्वारा नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लि०, दिल्ली (जिसे एतदोपरान्त प्राधिकृत नियंत्रक कहा जाएगा) को अयुध्या टैक्सटाइल मिल्स लि०, दिल्ली नामक उपरोक्त सम्पूर्ण उपक्रम का प्रबन्ध अपने अधिकार में लेने के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

- (1) प्राधिकृत नियंत्रक, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर दिये गये निदेशों का पालन करेगा;
- (2) प्राधिकृत नियंत्रक इस आदेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिये कार्यभार सम्प्रेलेगा। केन्द्रीय सरकार, यदि ग्राविध्यक समझेगी, तो उसमें पृथ्वी की इस प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति को रद्द कर सकती है।

2. यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिये प्रभावी रहेगा।

[सं० एफ०/९(८)/लिफ० पोल०/७१]

एस० के० सहगल,
संयुक्त सचिव, भारत सरकार।